[2013] 9 एस.सी.आर. 547

बलदेव सिंह

बनाम

पंजाब राज्य

(दाण्डिक अपील सं 1303/2005 आदि)

20 सितम्बर 2013

[ए.के. पटनायक और ज्ञान सुधा मिश्रा, जे.जे.]

दंड संहिता, 1860:

धारा 302 सपठित धारा 120-B - पुलिस दल ने परिवादी के परिवार के 7 सदस्यों को उठाया - पीड़ित वापस नहीं आए - धारा 364, 452, 120-B और 302 के तहत अधिनस्थ न्यायालयों द्वारा दोष सिद्धि - अभिनिर्धारित: यह साबित है कि अपीलकर्ताओं द्वारा अपहृत सात व्यक्तियों को विभिन्न पुलिस स्टेशनों और पुलिस स्टेशन के पास स्थित आवासीय छात्रावासों में देखा गया था - इस साक्ष्य के आधार पर, क्योंकि उनका पता नहीं चला है अथवा वे लापता हैं, न्यायालय यह नहीं कह सकता है कि दो अपीलकर्ताओं ने सात अपहृत व्यक्तियों की हत्या की है - न्यायालय के सामने कोई सामग्री प्रस्तुत नहीं की गई है जिससे प्रमाणित हो सके कि सात व्यक्तियों में से कोई भी या सातों व्यक्ति अंतिम बार जिस पुलिस

स्टेशन में रखे गए थे, वह अपीलकर्ताओं के नियंत्रण में था - ऐसे साक्ष्य की अनुपस्थिति में, धारा 302 के तहत अधिनस्थ न्यायालयों द्वारा अपीलकर्ताओं के खिलाफ दर्ज की गई दोष सिद्धि, तथ्यों या विधि अनुसार सही नहीं थी - अतः, धारा 302 सपठित धारा 120-B के तहत अपीलकर्ताओं की दोष सिद्धि अपास्त की जाती है।

धारा 364 और 452 - पुलिस दल द्वारा परिवार के सात सदस्यों को उठाया गया - पीड़ित वापस नहीं आए - अभिनिर्धारित: यह स्थापित है कि अपीलकर्ता परिवादी के घर तड़के सुबह गए और उसके परिवार के 7 सदस्यों को उठा लिया - अतः, अपीलकर्ताओं की धारा 364 और 452 के तहत दोष सिद्धि को उच्च न्यायालय द्वारा उचित रूप से पुष्ट किया था- धारा 452 के तहत तीन वर्षों की सजा और जुर्माना पुष्ट जाता है - हालांकि, मामले के तथ्यों में, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 220(1) के उदाहरण (h) को दृष्टिगत रखते हुए, क्योंकि सात व्यक्तियों को अपीलकर्ताओं द्वारा अपहृत किया गया था, उन्हें सात अपराधों के लिए दोषी पाया गया है और उन्हें धारा 364 के तहत प्रत्येक अपराध के लिए सजा दी जानी चाहिए थी - इसलिए, यह निर्देशित किया जाता है कि विचारण न्यायालय द्वारा अधिरोपित 4000/- रुपये की जुर्माना राशि और पांच वर्षों की कठोर कारावास की अवधि प्रत्येक अपहरण के सात अपराधों के लिए होगी और पांच वर्षों की कठोर कारावास की अवधि प्रत्येक अपहरण के

सात अपराधों के लिए साथ-साथ नहीं चलेगी, बल्कि क्रमिक रूप से चलेगी - आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 - धारा 220(1)/III(h).

विलंब / लैचेस:

एफआईआर दर्ज करने में देरी - अभिनिर्धारित: एफआईआर दर्ज करने में विलंब अक्सर अलंकरण और यह भी कि वास्तव में क्या हुआ है उसका विकृत संस्करण पेश करने का कारण बनता है, लेकिन प्रत्येक मामले के तथ्यों को देखकर पता लगाना होगा कि क्या एफआईआर दर्ज करने में विलंब अभियोजन पक्ष के मामले के लिए घातक है - इस मामले में, यह पर्याप्त साक्ष्य है कि परिवादी एक स्थानीय पुलिस स्टेशन,जो एक आरोपी-अपीलकर्ता के नियंत्रण में था, में शिकायत दर्ज करने के लिए डर रहा था - एफआईआर दर्ज करने में 2 महीने और 21 दिनों की देरी को तथ्यों और पेश किए गए साक्ष्य द्वारा स्पष्ट किया गया है - एफआईआर।

धारा 161 के तहत बयानों को दर्ज करने में विलंब - अभिनिर्धारित: परिवादी ने पहली शिकायत में ही अपीलकर्ताओं को उन व्यक्तियों के रूप में नामित किया था जिन्होंने उनके घर पर छापा मारा और उनके परिवार के सात सदस्यों को उठा लिया था, और इसलिए, तथ्य यह है कि गवाहों के बयानों को दर्ज करने में, एफआईआर दर्ज करने की तारीख से दो वर्षों की देरी हुई थी, इस संबंध में, उनकी साक्ष्य को संदिग्ध नहीं बनाती है।

साक्ष्य:

आरोपी के साथ गवाहों की शत्रुता- साक्ष्य - अभिनिर्धारित: इस तरह के गवाह के कथनों को न्यायालय द्वारा ध्यानपूर्वक जांचा जाना चाहिए इससे पहले कि इसे साबित माना जाए, लेकिन केवल शत्रुता के कारण, न्यायालय गवाह के कथनों को पूरी तरह से नकार नहीं सकती है।

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973:

धारा 161 और 162, स्पष्टीकरण - गवाह के न्यायालय में दर्ज किए गए साक्ष्य में धारा 161 के तहत दर्ज बयान के मुकाबले में सुधार- अभिनिर्धारित: धारा 162 के स्पष्टीकरण के मद्देनजर, जब तक कि धारा 161, सीआरपीसी के तहत दर्ज एक गवाह के बयान में छोड़ा गया हिस्सा महत्वपूर्ण और प्रासंगिक नहीं होता है, जिस संदर्भ में छोड़ा जाता है, तो यह न्यायालय में दर्ज गवाह के साक्ष्य के साथ विरोधाभास को प्रकट नहीं करेगा - इस प्रकरण में, अधिनस्थ न्यायालयों ने लोप को धारा 162 के स्पष्टीकरण अंतर्गत उल्लेखित विरोधाभासों के रूप में नहीं मानने का सही तरीके से विनिश्चय किया है।

अपीलकर्ता (जो कि एक डीएसपी और एक पुलिस कांस्टेबल है) और 9 अन्य लोगों को धारा 120-बी, 148, 452, 364, 365, 302 सपठित धारा 120-बी और धारा 201, आईपीसी के तहत दंडनीय अपराध करने के लिए विचारण किया गया था। अभियोजन पक्ष का मामला था कि 29-10-1991 को सुबह करीब 5:00 बजे, अपीलकर्ता और अन्य पुलिसकर्मियों ने

परिवादी (पीडब्ल्यू 13) के घर पर छापा मारा और उसके परिवार के सात सदस्यों को उठा लिया, जो इसके बाद कभी वापस नहीं आए। विचारण न्यायालयने अपीलकर्ताओं को धारा 452, 364 और 302 सपठित धारा 120-बी आईपीसी के तहत दोषी ठहराया और उन्हें विभिन्न अवधि की सजा सुनाई, जिसमें धारा 302 आईपीसी के तहत आजीवन कारावास भी शामिल था। उच्च न्यायालय ने अपील खारिज कर दी।

अपीलों को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए, न्यायालय द्वारा

अभिनिर्धारित: 1.1. इसमें कोई संदेह नहीं है कि एफआईआर दर्ज करने में देरी से अक्सर अलंकरण और वास्तविकता से परे क्या हुआ है उसका विकृत संस्करण पेश करने का कारण बनता है, लेकिन प्रत्येक मामले के तथ्यों को देखकर पता लगाना होगा कि क्या एफआईआर दर्ज करने में विलंब अभियोजन पक्ष के मामले के लिए घातक है। इस मामले में, पीडब्ल्यू-3 के साक्ष्य से स्पष्ट है कि पंजाब राज्य में आतंकवादी सक्रिय थे और पुलिस आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही थी और ऐसी स्थिति में, पीडब्ल्यू-3 को अपीलकर्ताओं, जिनमें से एक कई पुलिस स्टेशनों का नियंत्रण करने उप पुलिस अधीक्षक था और दूसरा एक पुलिस कांस्टेबल था, के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने में दुष्परिणामों का अंदेशा था। इसलिए, जब उनके परिवार के सात सदस्य 29.10.1991 को उठा लिए गए थे, तो पीडब्ल्यू-3 ने इस उम्मीद के साथ इंतजार किया कि उन्हें पुलिस

द्वारा रिहा कर दिया जाएगा और केवल तब जब उनके सभी प्रयास उन्हें रिहा करने में विफल हो गए, उन्होंने 19.01.1992 को शिकायत दर्ज की। तथ्य यह है कि परिवादी ने शिकायत को पुलिस स्टेशन के बजाय पुलिस महानिदेशक को संबोधित किया, यह पर्याप्त साक्ष्य है कि पीडब्ल्यू-3 को सर्वप्रथम स्थानीय पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करने का डर था जो अपीलकर्ता संख्या 1 के नियंत्रण में था। तथ्य परिस्थिति पर विचार करते हुए, पीडब्ल्यू-3 द्वारा पुलिस महानिदेशक, पंजाब को शिकायत दर्ज करने में 2 महीने और 21 दिनों की देरी को पीडब्ल्यू-3 द्वारा समझाया गया था और यह कोई मामला नहीं है जहां अभियोजन पक्ष को एफआईआर दर्ज करने में देरी के आधार पर अविश्वसनीय माना जा सके। [पैरा 16-17]

गौरी शंकर शर्मा. बनाम यूपी राज्य 1990 एससीआर 29 = 1990 (अनुपूरक) एस सी सी 656 - अवलंब लिया।

1.2. जहां तक साक्षियों के धारा 161 के बयानों को दर्ज करने में देरी का सवाल है, पीडब्ल्यू-3 और पीडब्ल्यू-4 के साक्ष्य से स्पष्ट है कि निर्दिष्ट तारीख और समय पर, अपीलकर्ता 3-4 वाहनों में आए और उनके परिवार के सात सदस्यों को जिप्सी में ले गए। आगे, 19.01.1992 को पीडब्ल्यू-3 द्वारा दर्ज पहली शिकायत में, उन्होंने अपीलकर्ताओं को उन व्यक्तियों के रूप में नामित किया है जिन्होंने उनके घर पर छापा मारा और उनके परिवार के सात सदस्यों को उठा लिया। इसलिए, एफआईआर दर्ज करने की तारीख

से दो वर्षों की देरी पीडब्ल्यू-3 और पीडब्ल्यू-4 और अन्य गवाहों के बयानों को दर्ज करने में, उनके साक्ष्य को संदेहपूर्ण नहीं बनाती है कि अपीलकर्ताओं ने निर्दिष्ट तारीख और समय पर उनके परिवार के सात सदस्यों को उठाया था। [पैरा 18]

जगजीत सिंह उर्फ जग्गा बनाम पंजाब राज्य 2005 (1)एससीआर 559 =2005 (3) एससीसी 689;आंध्र प्रदेश राज्य बनाम एस. स्वामीलता एवं अन्य 2009 (12) एससीआर 289 = 2009 (8) एससीसी 383- लागू होना नहीं पाया।

1.3. जहां गवाह और आरोपी के बीच पूर्व शत्रुता होती है, उस गवाह के साक्ष्य को न्यायालय द्वारा स्वीकार करने से पहले सावधानीपूर्वक परखा जाना चाहिए, लेकिन केवल ऐसी शत्रुता के कारण न्यायालय गवाह के साक्ष्य को पूरी तरह से अस्वीकार नहीं कर सकता। इसके अलावा, कुछ स्थितियों में एक अपराध के पीड़ित से संबंधित नहीं होने वाले गवाहों को खोज पाना मुश्किल होता है। अपीलकर्ताओं ने 29.10.1991 की सुबह 5.00 बजे परिवादी (पीडब्ल्यू-3) के घर पर जाकर उनके परिवार के सात सदस्यों को उठा लिया था और निर्दिष्ट समय पर घटना को देखने वाले व्यक्तियों को खोज पाना मुश्किल है। इसके अलावा, अपीलकर्ताओं में से एक उप पुलिस अधीक्षक था और, इसलिए, कोई भी व्यक्ति जांच अधिकारी के सामने या न्यायालय के सामने घटना का वर्णन करना पसंद नहीं करेगा। ऐसी स्थिति

में, न्यायालय को आरोपी के साथ शत्रुता रखने वाले गवाहों के साक्ष्य को सावधानीपूर्वक और सतर्कता से विचार करना होगा। इस तरह के सावधानीपूर्वक और सतर्क विचार के बाद, पीडब्ल्यू-3 के साक्ष्य को अस्वीकार करना मुश्किल है, जब उसे पीडब्ल्यू-4 के साक्ष्य के साथ-साथ पीडब्ल्यू-3 की तारीख 19.01.1992 (एक्सटी. पीबी) की शिकायत के साथ पुष्टि की जाती है, जिसे एफआईआर के रूप में पंजीकृत किया गया था। इसलिए, पीडब्ल्यू-3 और पीडब्ल्यू-4 के साक्ष्य को शत्रुता के आधार पर अस्वीकार नहीं किया जा सकता। [पैरा 20]

उत्तर प्रदेश राज्य बनाम किशनपाल एवं अन्य 2008 (11) एससीआर 1048 = 2008 (16) एससीसी 73 - अवलंब लिया।

1.4. पीडब्ल्यू-3 के बयान में धारा 161 सीआरपीसी के तहत दर्ज किए गए पीडब्ल्यू-3 के बयानों के मुकाबले में सुधार के तर्क के संबंध में, धारा 162 सीआरपीसी के व्याख्या के दृष्टिकोण से, जब तक कि धारा 161, सीआरपीसी के तहत दर्ज एक गवाह के बयान में छोड़ा गया हिस्सा महत्वपूर्ण और प्रासंगिक नहीं होता है, जिस संदर्भ में छोड़ा जाता है, तो यह न्यायालय में दर्ज गवाह के साक्ष्य के साथ विरोधाभास को प्रकट नहीं करेगा। पीडब्ल्यू-3 के साक्ष्य में निर्दिष्ट तिथि और समय पर उनके परिवार के सात सदस्यों को उनके घर से उठाए जाने के तथ्यों और पीड़ितों के नामों के संबंध में कोई लोप नहीं है जो उनके बयान धारा 161 सीआरपीसी

में किए गए हैं। विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय ने सही ढंग से विचार किया कि वाहनों की प्रकृति, संख्या और रंग और आए हुए लोगों की संख्या के साथ-साथ घटना के बाद क्या हुआ, इस संबंध में लोप किये गए कथनों को धारा 162, सीआरपीसी के व्याख्या द्वारा उल्लेखित विरोधाभास के रूप में महत्वपूर्ण लोप के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। इसलिए, उच्च न्यायालय ने ठीक तरह से अपीलकर्ताओं की धारा 364 और 452 आईपीसी के तहत सजा बरकरार रखी। [पैरा 21]

2.1. पीडब्ल्यू-3 से पीडब्ल्यू-6 के साक्ष्यों से यह स्पष्ट है कि अपीलकर्ताओं द्वारा अपहृत पीड़ितों को बाद में विभिन्न पुलिस स्थानों में और पुलिस स्थान के पास आवासीय क्वार्टरों में देखा गया था। न्यायालय के समक्ष कोई सामग्री प्रस्तुत नहीं की गई है जिससे यह प्रमाणित किया जा सके कि सात व्यक्तियों में से आखिरी पुलिस थाना जिसमें सात व्यक्तियों में से कोई भी रखा गया था, वह अपीलकर्ताओं के नियंत्रण में था। ऐसे साक्ष्य की अनुपस्थिति में, धारा 302 आईपीसी के तहत विचारण न्यायालयों द्वारा दर्ज दोष सिद्धि का पता लगाना न तो तथ्यों पर और न ही कानून पर सही था। [पैरा 27]

2.2. इस प्रकार, धारा 302 सपठित 120-बी, आईपीसी के तहत दो अपीलकर्ताओं की दोषसिद्धि को अपास्त किया जाता है, लेकिन धारा 364 और 452, आईपीसी के तहत उनकी सजा बरकरार रहती है। धारा 452,

आईपीसी के तहत दंडनीय अपराध के लिए तीन साल की कठोर कारावास और 3000/- रुपये का जुर्माना बरकरार रहता है। लेकिन धारा 364, आईपीसी के तहत सजा और जुर्माने के रूप में, सीआरपीसी की धारा 220(1) के उद्धरण (एच) के मद्देनजर, चूंकि सात व्यक्तियों का अपीलकर्ताओं द्वारा अपहरण किया गया था, उन्हें धारा 364 आईपीसी के तहत सात अपराधों के लिए दोषी पाया गया था, और उन्हें इन अपराधों में से प्रत्येक के लिए सजा दी जानी चाहिए। इस प्रकार, निर्देश दिया जाता है कि विचारण न्यायालय द्वारा लगाया गया 4000/- रुपये का जुर्माना और पांच साल की कठोर कारावास की अवधि, सात अपहरण अपराधों में से प्रत्येक के लिए होगी; और सात अपहरण अपराधों में से प्रत्येक के लिए पांच साल की कठोर कारावास की अवधि एक साथ नहीं चलेगी, बल्कि एक के बाद एक चलेगी। [पैरा 28]

महराज सिंह (लांस नायक) बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 1994 (5) एससीसी 188; विष्णु दावरे बनाम महाराष्ट्र राज्य 2004(9) एससीसी 431; राधा कुमार बनाम बिहार राज्य (झारखंड) 2005 (10) एससीसी 216; सुनील कुमार संभुदयाल गुप्ता (डॉ.) एवं अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य 2010 (15) एससीआर 452 =2010 (13) एससीसी 657; सहदेवन और अन्य बनाम तमिलनाडु राज्य 2012(4) एससीआर 366 = 2012 (6) एससीसी 403; एल आई सी भारत बनाम अनुराधा 2004 (3) एससीआर 629 2004 (10) एससीसी 131; पृथ्वीपाल सिंह एवं अन्य. बनाम पंजाब राज्य

और अन्य। 2012(14) एससीआर 862 = 2012 (1) एससीसी 10; गुलाम चौधरी एवं अन्य बनाम बिहार राज्य 2001 (3) पूरक. एससीआर 279 2001 (8) एससीसी 311; बादशाह और अन्य. बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2008 (2) एससीआर 766 2008 (3) - उल्लेखित।

न्यायिक निर्णय संदर्भ:

1990 SCR 29	अवलंब लिया	पैरा 17
2005 (1) SCR 559	लागु नहीं	पैरा 7
2009 (12) SCR 289	लागु नहीं	पैरा 7
2008 (11) SCR 1048	अवलंब लिया	पैरा 7
1994 (5) SCC 188	उल्लेख किया	पैरा 7
2004(9) SCC 431	उल्लेख किया	पैरा 7
2005(10) SCC 126	उल्लेख किया	पैरा 7
2010(15) SCR 452	उल्लेख किया	पैरा 7
2012(4) SCR 366	उल्लेख किया	पैरा 10
2004(3) SCR 629	उल्लेख किया	पैरा 11
2012(14) SCR 862	उल्लेख किया	पैरा 12
2001(3) Suppl. SCR 279	उल्लेख किया	पैरा 15

2008(2) SCR 766 उल्लेख किया पैरा 15

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील संख्या 1303/2005

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, चंडीगढ़ के निर्णय एवं आदेश दिनांक 06.04.2005 अंतर्गत आपराधिक अपील संख्या 221/ 1998 -डीबी

एवं

दाण्डिक अपील सं. 1380/2005

अमरेंदर सरन, कवलजीत कोचर, कुसुम चौधरी अपीलकर्ता की ओर से।

वी. मधुकर, एएजी, परितोष अनिल, अनिवता कौशिक, सृजिता माथुर, कुलदीप सिंह प्रतिवादी की ओर से ।

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति ए के पटनायक द्वारा सुनाया गया:

1. हस्तगत अपीलें विशेष अनुमति याचिका अंतर्गत आर्टिकल 136 के तहत पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के समेकित निर्णय के खिलाफ हैं जो कि 06.04.2005 को आपराधिक अपील संख्या 221-DB/1998 में पारित हुआ था।

प्रकरण के तथ्य:

2. संक्षेप में तथ्य यह हैं कि इंदर सिंह ने 19.01.1992 को रजिस्टर्ड पोस्ट मय पावती पुलिस महानिदेशक, पंजाब को एक आवेदन भेजा था, जिसमें उनके परिवार के सात सदस्यों को रिहा करने का आग्रह किया गया था। आवेदन में इंदर सिंह ने आरोप लगाया कि 29.10.1991 को सुबह 5 बजे बलदेव सिंह, उप पुलिस अधीक्षक, और बलविंदर सिंह, पुलिस कांस्टेबल (इस मामले के अपीलकर्ता) और अन्य पुलिसकर्मियों ने उनके घर पर छापा मारा और उनके परिवार के सात सदस्यों को पकड़ लिया। वे सदस्य हैं साधु सिंह (उनके पिता), हरदेव सिंह (उनके बेटे), गुरदीप सिंह और अमनजीत सिंह (उनके भाई), शरणजीत सिंह (उनके छोटे भाई सज्जन सिंह का बेटा) और दविंदर सिंह और सुखदेव सिंह (उनके छोटे भाई खजान सिंह के दो बेटे)। इंदर सिंह ने उपरोक्त आवेदन में आगे कहा कि उन्होंने अपने परिवार के सदस्यों को, जो पकड़े गए थे, फतेहगढ़ चूरियां, पुलिस थाना कलानौर, डेरा बाबा नानक और पुलिस थाना कथू नंगल में देखा था और 08.01.1992 को, उनके बेटे सरवन सिंह ने इन व्यक्तियों को अमृतसर में पुलिस वाहन में देखा था। आवेदन में, इंदर सिंह ने कहा कि उन्हें डर था कि अपीलकर्ता-बलदेव सिंह उनके परिवार के सदस्यों को मार सकते हैं या किसी मामले में फंसा सकते हैं और उन्होंने आग्रह किया कि उन्हें पुलिस की अवैध हिरासत से जल्द से जल्द रिहा किया जाए। 21.03.1994 को दी गई मेमो के अनुसार, पुलिस महानिरीक्षक, अपराध शाखा ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मजीठा को मामला पंजीकृत करने

के लिए निर्देशित किया और इसके अनुसार 23.03.1994 को पुलिस थाना, कथुनांगल, जिला मजीठा में भारतीय दंड संहिता की धारा 364 के तहत एक औपचारिक FIR दर्ज की गई। जांच के बाद, नौ आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ आरोप तय किए गए, जिनमें अपीलकर्ता भी शामिल थे और संशोधित आरोपों के अनुसार, नौ आरोपी व्यक्तियों को धारा 120-B, 148, 452, 364, 365, 302 सपठित 120-B और 201, IPC के तहत अपराधों के लिए मुकदमा चलाया गया।

3. मुकदमे में, चौदह अभियोजन साक्षी परीक्षित किए गए। इंदर सिंह को पीडब्लू-3 के रूप में परीक्षित किया गया और उन्होंने बताया कि 29.10.1991 को दो अपीलकर्ताओं ने बीस से पच्चीस व्यक्तियों के साथ वाहनों में आकर उनके घर पहुंचे और उनके परिवार के सात सदस्यों को ले जाया। पीडब्लू-3 ने आगे गवाही दी कि वह और उसके अन्य संबंधी उच्च अधिकारियों से मिले थे, लेकिन सात व्यक्तियों को छोड़ने की उनकी सभी कोशिशें कोई परिणाम नहीं दे सकीं। पीडब्लू-3 के साक्ष्य की पुष्टि उनके भाई सज्जन सिंह ने की, जिन्हें पीडब्लू-4 के रूप में परीक्षित किया गया, साथ ही जरनैल सिंह, पीडब्लू-3 के एक संबंधी, जिन्हें पीडब्लू-5 के रूप में परीक्षित किया गया। सरवन सिंह, पीडब्लू-3 के पुत्र, को भी पीडब्लू-6 के रूप में परीक्षित किया गया और उन्होंने कहा कि 08.01.1992 को उन्होंने अमृतसर में बस स्टैंड के पास दुकान पर मौजूद रहते हुए एक पुलिस जिप्सी को सड़क पर जाते हुए देखा और देखा कि उनके भाई हरदेव सिंह

वाहन में बैठे थे और यहां तक कि उन्होंने अपना हाथ उठाकर संकेत दिया। उन्होंने यह भी कहा कि वाहन में अन्य व्यक्ति भी बैठे थे, लेकिन उन्होंने उन्हें नहीं देखा और वाहन का पीछा करने का प्रयास किया, लेकिन वे ऐसा नहीं कर सके। अपीलकर्ताओं ने भी अपने बचाव में ग्यारह साक्षियों की परीक्षा की, जिन्होंने यह बताया कि उन्होंने अभियोजन द्वारा आरोपित किसी भी व्यक्ति को हिरासत में नहीं लिया।

4. विचारण न्यायालय ने अपीलकर्ताओं के बचाव को खारिज कर दिया और अपीलकर्ताओं को धारा 452, 364, और 302 सपठित 120-B, IPC के तहत, जो निर्णय 30.03.1998 को दिया गया था, के अंतर्गत दोषी ठहराया। इसके बाद विचारण न्यायालय ने अपीलकर्ताओं को सजा के प्रश्न पर सुनवाई की और उन्हें धारा 452, IPC के तहत सदोष अवरोध एवं गृह अतिचार के अपराध के लिए तीन साल का कठोर कारावास और 3,000 रुपये का जुर्माना, साधु सिंह, गुरदीप सिंह, हरदेव सिंह, अमनजीत सिंह, शरणजीत सिंह, दविंदर सिंह और सुखदेव सिंह के अपहरण के अपराध के लिए पांच साल की कठोर कारावास और 4,000 रुपये का जुर्माना धारा 364 IPC के तहत, और साधु सिंह, गुरदीप सिंह, हरदेव सिंह, अमनजीत सिंह, शरणजीत सिंह, दविंदर सिंह और सुखदेव सिंह की हत्या के अपराध के लिए धारा 302 सपठित 120-B, IPC के तहत आजीवन कठोर कारावास सजा और 50,000 रुपये का जुर्माना सुनाया। अपीलकर्ताओं ने हाईकोर्ट में आपराधिक अपील संख्या 221-DB / 1998 के लिए अपील दायर की और

चुनौतीग्रस्त निर्णय दिनांक 06.04.2005 के अनुसार, हाई कोर्ट ने अपील खारिज कर दी।

अपीलकर्ताओं की ओर से दलीलें:

5. श्री अमरेंद्र शरण, जो वरिष्ठ वकील हैं और अपीलकर्ताओं की ओर से उपस्थित हुए हैं, ने सुझाव दिया है कि जबकि घटना का कथित तौर पर 29.10.1991 को होना बताया गया था, FIR को 19.01.1992 को दर्ज किया गया और इस प्रकार FIR दर्ज करने में दो महीने और इक्कीस दिन की देरी हुई। उन्होंने कहा कि अभियोजन पक्ष ने यह देरी इस तरह से समझाई है कि परिवादी ने पहले वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और पुलिस महानिदेशक से संपर्क किया और उसके बाद न्यायालयों में और इसके बाद इस न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका भी दायर की गई और केवल उसके बाद ही शिकायत को एक FIR के रूप में दर्ज किया गया। श्री शरण ने यह कहा कि पीडब्लू-3 समृद्ध किसान परिवार का सदस्य था और उसका बेटा पीडब्लू-6 पुलिस में काम कर रहा था और उसका दोस्त पीडब्लू-5 पंजाब राज्य कांग्रेस समिति का सदस्य भी था और उसकी राज्य के मुख्यमंत्री तक आसान पहुंच थी और, इसलिए, अभियोजन पक्ष द्वारा दी गई स्पष्टीकरण कि FIR दर्ज करने में दो महीने और इक्कीस दिन की देरी हुई, को न्यायालय द्वारा अस्वीकार किया जाना चाहिए। उन्होंने मेहराज सिंह (लांस नायक) बनाम उत्तर प्रदेश राज्य [(1994) 5 SCC 188] के निर्णय

का हवाला दिया, जिसमें इस न्यायालय ने कहा है कि FIR दर्ज करने में देरी से अक्सर वृद्धि और विकृत या अतिशयोक्ति संस्करण की शुरुआत होती है और FIR अपनी महत्त्व और प्रमाणिकता खो देती है।

6. श्री शरण ने आगे कहा कि पर्याप्त साक्ष्य थे जो यह दिखाते थे कि परिवादी और अपीलकर्ताओं के बीच शत्रुता थी। इस संदर्भ में, उन्होंने पीडब्लू-3 के साक्ष्य का हवाला दिया, जो परिवादी स्वयं थे, कि अपीलकर्ता-बलदेव सिंह के भाई को 18.10.1991 को आतंकवादियों ने अगवा किया था और अपीलकर्ता-बलदेव सिंह का यह मानना था कि गुरदीप सिंह (पीडब्लू-3 का भाई) ने कुलदीप सिंह को अगवा करने में मदद की थी और इससे पहले कुंदन सिंह, जो अपीलकर्ताओं के साथ एक सह-आरोपी थे लेकिन विचारण न्यायालय द्वारा बरी कर दिए गए थे, ने पीडब्लू-3 के परिवार से किसी लड़की को पीडब्लू-3 के बेटे हरदेव सिंह से शादी करने के लिए स्वीकार करने के लिए कहा था, लेकिन हरदेव सिंह ने प्रस्ताव को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि जैसे कि पीडब्लू-3 के परिवार और अपीलकर्ताओं के बीच शत्रुता थी, पीडब्लू-3 ने अपीलकर्ताओं के खिलाफ झूठी शिकायत दर्ज की है।

7. श्री शरण ने आगे कहा कि पीडब्लू-3 और पीडब्लू-4 का साक्ष्य, जिस पर विचारण न्यायालय और हाई कोर्ट ने अपीलकर्ताओं को दोषी ठहराने के लिए भरोसा किया, विश्वसनीय नहीं है क्योंकि घटना के दो साल

बाद पहली बार जुलाई, 1994 में धारा 161, सीआरपीसी के तहत बयान दर्ज किए गए थे और यह तथ्य जांच अधिकारी (पीडब्लू-10) द्वारा स्वीकार किया गया है, जिन्होंने बयान दर्ज किए। उन्होंने इस न्यायालय के निर्णयों जगजीत सिंह उर्फ जग्गा बनाम पंजाब राज्य [(2005) 3 SCC 689] और आंध्र प्रदेश राज्य बनाम एस. स्वर्णलता और अन्य [(2009) 8 SCC 383] का हवाला दिया है, जिसमें यह कहा गया है कि जांच के दौरान एक गवाह की परीक्षा में देरी को यदि ठीक से समझाया नहीं जाता है तो यह गवाह के साक्ष्य की विश्वसनीयता के बारे में गंभीर संदेह पैदा करता है।

8. श्री शरण ने पीडब्लू- 3 के जमा के बयान में उसके धारा 161, सीआरपीसी के तहत जांच के दौरान दर्ज किए गए बयानों के दौरान की गई कई सुधारों का संदर्भ दिया। उन्होंने अशोक विष्णु दवरे बनाम महाराष्ट्र राज्य [(2004) 9 SCC 431], राधा कुमार बनाम बिहार राज्य (अब झारखंड) [(2005) 10 SCC 216] और सुनील कुमार संभुदयाल गुप्ता (डॉक्टर) और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य [(2010) 13 SCC 657] का हवाला दिया, जिसमें इस न्यायालय ने साक्षीगत गवाहों के साक्ष्य को उनके धारा 161, सीआरपीसी के तहत दर्ज की गई बयानों के ऊपर किए गए सुधारों के कारण विश्वसनीय नहीं माना है।

9. श्री शरण ने सुझाव दिया कि पुलिसकर्मी, जैसे कि एसएसपी सीता राम और एसएसपी हरदीप सिंह ढिल्लोन, जिनके नाम पीडब्लू-3, पीडब्लू-4

और पीडब्लू-5 के साक्ष्य में दिखाई देते हैं, सामग्री गवाह थे और फिर भी अभियोजन पक्ष ने उनकी जांच नहीं की है। उन्होंने सुझाव दिया कि इसी तरह, सुखबन्स कौर भिंडर, सांसद, और बेअंत सिंह, राज्य के मुख्यमंत्री, जिनके नाम भी पीडब्लू-3 के साक्ष्य में आए हैं, सामग्री गवाह थे, लेकिन उनकी जांच नहीं की गई है। उन्होंने सुझाव दिया कि उनके साक्ष्य से अभियोजन पक्ष के मामले पर पर्याप्त रोशनी पड़ती और न्यायालय को इन सामग्री गवाहों की जांच न करने के लिए अभियोजन पक्ष के प्रतिकूल निष्कर्ष निकालना चाहिए।

10. श्री शरण ने सुझाव दिया है कि रिकॉर्ड पर कोई भी साक्ष्य नहीं है जो यह दिखाता हो कि पुलिस द्वारा अपहृत सात व्यक्तियों को अपीलकर्ताओं ने मार डाला है। उन्होंने इस न्यायालय के निर्णय का हवाला दिया है कर्नाटक राज्य बनाम एम.वी. महेश [(2003) 3 SCC 353] में जिसमें कहा गया है कि यदि निश्चित साक्ष्य नहीं होते हैं कि बीना को मार डाला गया था, तो अभियुक्त को केवल इस परिस्थिति पर दोषी नहीं ठहराया जा सकता था कि अभियुक्त और बीना आखिरी बार साथ में देखे गए थे। उन्होंने सुझाव दिया है कि इस मामले में, पीडब्लू-3, पीडब्लू-4 और पीडब्लू-5 ने कहा है कि उन्होंने सात व्यक्तियों को फतेहगढ़ चुरियाँ पुलिस थाने और कलानौर पुलिस थाने में देखा था और पीडब्लू-6 ने आगे कहा है कि उसने 08.01.1992 को अमृतसर में एक पुलिस वैन में अपने भाई हरदेव को देखा और पहचाना था। श्री शरण ने सुझाव दिया है कि

इसलिए इन तथ्यों पर, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 लागू नहीं होती थी और अपीलकर्ताओं पर यह साबित करने का भार नहीं था कि उन्होंने सात व्यक्तियों की हत्या नहीं की थी जो उनके द्वारा अपहृत किए गए थे। उन्होंने सहादेवन और अन्य बनाम तमिलनाडु राज्य [(2012) 6 SCC 403] में इस न्यायालय द्वारा कहा गया है कि अंतिम दृष्टा सिद्धांत को अभियोजन पक्ष के पूरे मामले को ध्यान में रखते हुए लागू किया जाना चाहिए और इस बिंदु के पहले और बाद की परिस्थितियों को ध्यान में रखना चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया है कि यदि इस न्यायालय द्वारा सहादेवन और अन्य बनाम तमिलनाडु राज्य (उपरोक्त) में निर्धारित सिद्धांत को लागू किया जाता है तो अपीलकर्ताओं को सात व्यक्तियों के हत्या के अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता।

11. श्री शरण ने आगे कहा कि न्यायालय के सामने कोई भी साक्ष्य नहीं है कि सात व्यक्ति मृत हैं और जीवित नहीं हैं और विचारण न्यायालय ने भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 108 को लागू करके सात व्यक्तियों को मृत मानने का गलत निष्कर्ष निकाला है। उन्होंने इस न्यायालय के निर्णय एलआईसी ऑफ इंडिया बनाम अनुराधा [(2004) 10 SCC 131] का हवाला दिया, जिसमें भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 108 के पीछे के सिद्धांत की व्याख्या की गई है। उन्होंने सुझाव दिया कि किसी भी मामले में, यदि अपीलकर्ताओं के खिलाफ सात व्यक्तियों की हत्या के लिए धारा 302, आईपीसी के तहत कोई साक्ष्य था, तो उसे न्यायालय ने धारा 313,

सीआरपीसी के तहत अपीलकर्ताओं स्पष्टीकरण पूछना चाहिए था, लेकिन ऐसा इस मामले में नहीं किया गया है। उन्होंने दृढ़ता से तर्क दिया कि अपीलकर्ताओं का सात व्यक्तियों की हत्या के अपराध में धारा 302, आईपीसी के तहत बिना किसी साक्ष्य के दोषी ठहराया गया है।

राज्य की ओर से दलीलें:

12. श्री वी. मधुकर, जो पंजाब राज्य के लिए पेश हुए अधिवक्ता हैं, ने अपने जवाब में कहा कि इस मामले में हालांकि पीडब्लू-3 ने 19.01.1992 को शिकायत दर्ज की थी, लेकिन कुछ समय तक कुछ भी नहीं हुआ और, इसलिए, पीडब्लू-3 ने इस न्यायालय में एक बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की ताकि उसके परिवार के सात सदस्यों की रिहाई सुनिश्चित हो सके और 15.09.1994 को इस न्यायालय ने एक आदेश पारित किया कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा जांच की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस न्यायालय के उक्त आदेश के अनुपालन में, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 15.12.1994 प्रस्तुत की और उसके बाद पंजाब पुलिस की अपराध शाखा द्वारा जांच की गई और दोनो अपीलकर्ताओं और अन्य के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया गया। उन्होंने कहा कि इस मामले में पीडब्लू-3 की ओर से एफआईआर में देरी होने का कारण यह हो सकता है कि शिकायत पुलिस कर्मियों के खिलाफ थी और पीडब्लू-3 यह सोच रहा होगा कि क्या ऐसी शिकायत दर्ज की जाए

या नहीं। उन्होंने कहा कि इसलिए, यह एक असाधारण मामला था और इस न्यायालय ने प्रीतिपाल सिंह और अन्य बनाम पंजाब राज्य और अन्य [(2012) 1 SCC 10] में कहा है कि ऐसी असाधारण परिस्थिति में, न्यायालय को विचित्र तथ्यों का ध्यान रखना होगा और कानून को उसी के अनुसार नवीनीकृत करना होगा। उन्होंने सुझाव दिया कि इस असाधारण तथ्य में, जिसमें पीडब्लू-3 को एफआईआर दर्ज करनी थी, न्यायालय को एफआईआर दर्ज करने में हुई देरी को नजरअंदाज करना चाहिए।

13. श्री मधुकर ने आगे सुझाव दिया कि पीडब्लू-3, पीडब्लू-4 और पीडब्लू-5 के साक्ष्य मामले के महत्वपूर्ण पहलुओं पर हैं कि अपीलकर्ताओं ने 29.10.1991 को पीडब्लू-3 के परिवार के सात सदस्यों को हिरासत में लिया और यह पीडब्लू-3 का मामला था जिसने उसने 19.01.1992 को दर्ज की गई शिकायत में किया था और जांच के दौरान धारा 161, सीआरपीसी के तहत दर्ज की गई उसकी बयान में भी किया था। धारा 161, सीआरपीसी के तहत दर्ज की गई बयानों में जो चूक की गई हैं, जो कि न्यायालय में गवाहों के साक्ष्य के दौरान पूरी की गई हैं, वे इस मूल अभियोजन कहानी से विचलित नहीं होते हैं और, इसलिए, ये "विरोधाभास" नहीं हैं जिन्हें सीआरपीसी की धारा 162 के व्याख्यान के अंतर्गत कवर किया गया है। उन्होंने आगे सुझाव दिया कि इस असाधारण मामले में धारा 161, सीआरपीसी के तहत बयानों की देरी से दर्ज करने को अभियोजन पक्ष के मामले के लिए घातक नहीं माना जाना चाहिए क्योंकि मुख्य अभियोजन

कहानी कि अपीलकर्ताओं ने पीडब्लू-3 के परिवार के सात सदस्यों का अपहरण किया है, इसे सभी के द्वारा निरंतर दोहराया गया है, 19.01.1992 को शिकायत बनाने की तारीख से लेकर न्यायालय द्वारा गवाहों की जांच की तारीखों तक। उन्होंने सुझाव दिया कि पीडब्लू-3 के साक्ष्य से स्पष्ट होगा कि अपीलकर्ताओं का पीडब्लू-3 के परिवार के सात सदस्यों का अपहरण करने का उद्देश्य स्पष्ट रूप से प्रतिशोध था और इसलिए विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय ने पीडब्लू-3, पीडब्लू-4 और पीडब्लू-5 के साक्ष्य को सही माना।

14. श्री मधुकर ने सुझाव दिया कि सात अन्य पुलिसकर्मी जो अपीलकर्ताओं के साथ पीडब्लू-3 के परिवार के सात सदस्यों का अपहरण करने गए थे, उन्हें अभियोजन गवाह के रूप में परीक्षण नहीं किया गया क्योंकि वे भी आरोपी व्यक्ति थे और इन सात व्यक्तियों, अर्थात् कुंदन सिंह, सुखविंदर सिंह, बलविंदर सिंह, गुरमुख सिंह, अमरीक सिंह, निर्मल सिंह और रणधीर सिंह को विचारण न्यायालय द्वारा बरी कर दिया गया है। उन्होंने सुझाव दिया कि सिता राम, एसएसपी, बटाला के संबंध में रिकॉर्ड पर आई केवल साक्ष्य यह है कि उनसे एक संदेश प्राप्त हुआ था कि सात व्यक्तियों को उनके कार्यालय से प्राप्त किया जाएगा। उन्होंने सुझाव दिया कि अगर सिता राम, एसएसपी का परीक्षण किया गया होता तो वह केवल इनकार करता कि उसने ऐसा संदेश दिया था और इसलिए सिता राम,

एसएसपी के गवाह के रूप में परीक्षित नहीं होना अभियोजन पक्ष के खिलाफ नहीं माना जाना चाहिए।

15. श्री मधुकर ने दृढ़ता से सुझाव दिया कि अपीलकर्ता-बलदेव सिंह पुलिस विभाग में एक डीएसपी था और उसके अधीन सभी पुलिस स्टेशनों पर नियंत्रण था और अगर इस तथ्य के साथ-साथ यह तथ्य भी लिया जाए कि अपीलकर्ता-बलदेव सिंह ने पीडब्लू-3 के परिवार के सात सदस्यों का अपहरण किया, तो उस पर धारा 106 के तहत भारतीय साक्ष्य अधिनियम में उसके द्वारा अपहृत सात व्यक्तियों के साथ क्या हुआ, इसका भार उस पर था। उन्होंने सुझाव दिया कि जैसा कि अपीलकर्ताओं ने अपने ज्ञान के तथ्यों, विशेष रूप से साबित करने के इस भार को पूरा नहीं किया है, विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय ने सही तरीके से निर्धारित किया कि अपीलकर्ताओं ने सात अपहृत व्यक्तियों की हत्या की है। इस तर्क के समर्थन में, उन्होंने इस न्यायालय के फैसलों राम गुलाम चौधरी और अन्य बनाम बिहार राज्य [(2001) 8 SCC 311] और बादशाह और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य [(2008) 3 SCC 681] का हवाला दिया। उन्होंने सुझाव दिया कि इन दो मामलों में यह निर्धारित किया गया था कि यहां तक कि अगर किसी व्यक्ति के हत्या का आरोप लगाया गया था, तो अगर मृतक का शव प्राप्त नहीं हुआ, तो धारा 302, आईपीसी के तहत हत्या के लिए दोषी ठहराया जा सकता है, यदि मजबूत परिस्थितिक साक्ष्य मौजूद है और यदि अभियुक्त विशेष रूप से उसके ज्ञान के तथ्यों के बारे में कोई

स्पष्टीकरण पेश नहीं कर पाता है, जैसा कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के तहत प्रदान किया गया है। उन्होंने सुझाव दिया कि इसलिए यह एक ऐसा मामला नहीं है जिसमें इस न्यायालय को अपीलकर्ताओं के खिलाफ विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा दर्ज की गई समान तथ्य निष्कर्षों में हस्तक्षेप करना चाहिए और अपील को खारिज कर देना चाहिए।

न्यायालय के निष्कर्ष:

16. हमें यह निर्णय करना होगा कि क्या एफआईआर में 2 महीने और 21 दिनों की देरी अभियोजन पक्ष की कहानी को अविश्वसनीय बना देती है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि एफआईआर दर्ज करने में देरी से अक्सर अलंकरणकारी होती है और जो कुछ वास्तव में हुआ हो सकता है, उसका विकृत संस्करण पेश किया जाता है, लेकिन प्रत्येक मामले के तथ्यों को देखकर पता लगाना होगा कि क्या एफआईआर में देरी अभियोजन पक्ष के लिए घातक है। वर्तमान मामले में, हम पाते हैं कि पीडब्लू-3 के साक्ष्य से यह पता चलता है कि पंजाब राज्य में आतंकवादी सक्रिय थे और पुलिस आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही थी और ऐसी स्थितियों में, पीडब्लू-3 अपीलकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के दुषपरिणामों को लेकर चिंतित था, जिनमें से एक उप पुलिस अधीक्षक था जो कई पुलिस स्टेशनों पर नियंत्रण कर रहा था और दूसरा एक पुलिस कांस्टेबल

था। इसलिए, जब उसके परिवार के सात सदस्यों को 29.10.1991 को उठा लिया गया, पीडब्लू-3 ने 2 महीने और 21 दिनों तक इंतजार किया उम्मीद में कि उन्हें पुलिस द्वारा रिहा कर दिया जाएगा और केवल उनके सभी प्रयासों के बाद जब उन्हें रिहा करने की कोशिशें विफल रहीं, तब उन्होंने 19.01.1992 को शिकायत दर्ज की (पीबी डॉक्यूमेंट)। यह तथ्य कि परिवादी ने शिकायत (एक्स. पीबी) को पुलिस स्टेशन के बजाय पंजाब पुलिस के महानिदेशक को संबोधित किया, इस बात का पर्याप्त साक्ष्य है कि पीडब्लू-3 ने स्थानीय पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करने से डर लगा था जो अपीलकर्ता बलदेव सिंह के नियंत्रण में था।

17. इस बिंदु को स्पष्ट करने के लिए, हम गौरी शंकर शर्मा बनाम राज्य उत्तर प्रदेश [1990 (सप्लीमेंट) SCC 656] के संदर्भ में कह सकते हैं। इस मामले में, तथ्य यह थे कि राम धीरज की मौत उनकी गिरफ्तारी के बाद हुई चोटों के कारण हो गई थी जब वह पुलिस हिरासत में थे। अभियोजन का संस्करण यह था कि उसे 19.10.1971 को पुलिस हिरासत में आरोपी संख्या 1 और उसके दो साथियों द्वारा पीटा गया था जब उसे उसके निवास से गिरफ्तार करके पुलिस थाने लाया गया था। हालांकि उच्च न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकाला कि गिरफ्तारी के बाद मृतक को पीटा गया था, लेकिन उच्च न्यायालय ने पुलिस स्टेशन के स्टेशन हाउस अधिकारी की संलिप्तता के संबंध में तीन गवाहों की प्रत्यक्ष गवाही पर भरोसा करने से इनकार कर दिया और तीन अभियोजन गवाहों के सबूतों

को खारिज करने के लिए एक कारण यह था कि टेलीग्राम PW-5 द्वारा भेजा गया था जिसने स्टेशन हाउस अधिकारी से 23.10.1971 को मृतक की पिटाई न करने का अनुरोध किया था, जबकि अभियोजन का मामला यह था कि मृतक के व्यक्ति पर चोटें 19.10.1971 की शाम को करीत हुई थीं। इस न्यायालय ने माना कि उच्च न्यायालय ने यह विवेचना करने में विफल रहा है कि कोई भी एक पुलिस अधिकारी के खिलाफ इतनी गंभीर शिकायत करने का निर्णय करने से पहले दो बार सोचता है और तीन गवाहों के सबूतों को देरी के कारण खारिज करने के लिए कोई गंभीर देरी नहीं हुई थी। हमारे विचार में, तथ्य परिस्थितियों को देखते हुए, PW-3 द्वारा पंजाब के पुलिस महानिदेशक को शिकायत दर्ज करने में हुई 2 महीने और 21 दिनों की देरी को PW-3 द्वारा समझाया गया है और यह कोई मामला नहीं है जहां अभियोजन पक्ष को FIR दर्ज करने में हुई देरी के कारण पर अविश्वास किया जा सकता है।

18. आगे हम श्री शरण के तर्क पर विचार कर सकते हैं कि विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय को गवाहों के सबूतों पर भरोसा नहीं करना चाहिए था जब उनके बयान धारा 161, सी.आर.पी.सी. के तहत पहली बार जुलाई, 1994 में दर्ज किए गए थे, घटना और FIR की दर्जी के दो साल बाद। श्री शरण द्वारा उद्धृत जगजीत सिंह उर्फ़ जग्गा बनाम पंजाब (सुप्रा) में संबंधित तथ्य यह थे कि PW-6, जो 7 वर्षीय युवती थी और जगजीत सिंह के गाँव के अलावा एक अलग गाँव में रहती थी, उसने अपने पहले

बयानों में यह नहीं कहा था कि वह उसे जानती है, लेकिन जाँच अधिकारी द्वारा धारा 161, सी.आर.पी.सी. के तहत दर्ज किए गए उसके बयान में उसने दावा किया कि वह उसे जानती है और इन तथ्यों पर इस न्यायालय ने कहा कि उसके पहले बयानों में उसने उसका नाम नहीं लिया और जाँच के दौरान उसकी जाँच में देरी से भी उसके देरी से जाँच की जाने की कोई स्पष्टीकरण नहीं होने की वजह से गंभीर संदेह पैदा होता है और आगे यह कहा कि हालांकि वह घटना की गवाह हो सकती है, लेकिन वह जगजीत सिंह को नहीं जानती और उसे उससे पहले जानने या देखने का कोई अवसर नहीं था और उसने उसे अपने पिता के कहने पर शामिल किया जब उसका बयान जाँच अधिकारी द्वारा दर्ज किया गया। वर्तमान मामले के तथ्यों में, दूसरी ओर, PW-3 और PW-4, जिन्होंने न्यायालय के सामने अपने सबूतों में कहा है कि 29.10.1991 को अपीलकर्ता बलदेव सिंह और बलविंदर सिंह 3-4 वाहनों में आए और उनके परिवार के सात सदस्यों को जिप्सी में ले गए और दो अपीलकर्ता जानते थे जो गाँव राम दिवाली में रहते थे, जो PW-3 और PW-4 के गाँव से छोटी दूरी पर था। इसके अलावा, पहली शिकायत जो PW-3 ने 19.01.1992 को दर्ज की थी, उसमें PW-3 ने अपीलकर्ता बलदेव सिंह और बलविंदर सिंह को उन लोगों के रूप में नामित किया था जिन्होंने उनके घर पर छापा मारा था और उनके परिवार के सात सदस्यों को उठा लिया था। इसलिए, यह तथ्य कि FIR दर्ज करने की तारीख से दो साल की देरी और PW-3 और PW-4 और

अन्य गवाहों के बयान दर्ज करने में देरी हुई थी, इसे संदिग्ध नहीं बनाता है कि अपीलकर्ता ने 29.10.1991 को सुबह 5.00 बजे उनके परिवार के सात सदस्यों को उठाया था।

19. श्री शरण द्वारा उद्धृत किया गया है, कि राज्य आंध्र प्रदेश बनाम एस. स्वर्णलता और अन्य (सुप्रा) में भी अभियोजन पक्ष ने PW-3, एक टैक्सी चालक के सबूतों पर भरोसा किया, जिसने दावा किया था कि उसने आरोपी व्यक्तियों को उस घर तक पहुंचाया था जहां दो व्यक्तियों की हत्या हुई थी और उसने यह भी कहा था कि आरोपी व्यक्तियों ने घर में प्रवेश किया और उससे कहा कि वह उस जगह पर रुका रहे और आधे घंटे बाद सभी लोग घर से बाहर आ गए और उससे कहा कि उन्हें रिंग रोड, दिलसुखनगर में छोड़ दे। इस न्यायालय ने पाया कि PW-3 ने धारा 161, सी.आर.पी.सी. के तहत अपने बयान में केवल दो आरोपी व्यक्तियों के नाम उल्लेख किए थे, लेकिन न्यायालय के सामने अपनी गवाही में, उसने छह आरोपी व्यक्तियों के नाम लिए और इसके अलावा PW-3 को जांच अधिकारी ने उस संदेहित घर पर नहीं ले जाया जहाँ घटना घटित हुई थी, ताकि वह उस घर की पहचान कर सके। इन तथ्यों पर, इस न्यायालय ने कहा कि PW-3 का बयान जो 31.01.1999 को जांच अधिकारी द्वारा दर्ज किया गया था, जबकि मृतक की हत्या 03.12.1997 को हुई थी, विशेषकर तब जब उसका बयान धारा 164, सी.आर.पी.सी. के तहत भी दर्ज किया गया था, धारा 161, सी.आर.पी.सी. के तहत उसके बयान के दर्ज होने से

पहले, विश्वसनीय नहीं था। इस तरह, इस मामले के विचित्र तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय द्वारा जाँच अधिकारी द्वारा धारा 161, सी.आर.पी.सी. के तहत गवाहों के बयान को दर्ज करने में हुई देरी के खिलाफ विचार किया गया। वर्तमान मामले के तथ्यों में, जाँच का लक्ष्य डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस और कई अन्य पुलिस अधिकारियों के खिलाफ था और जाँच पुलिस विभाग के क्राइम ब्रांच के जाँच अधिकारी द्वारा की जा रही थी। इसलिए, पुलिस में जाँच के खिलाफ बाधा थी और यह केवल इस न्यायालय के हस्तक्षेप के कारण था, जिसके तहत यह मामला रिट याचिका (दाण्डिक) संख्या 221 ऑफ 1994 में देरी के कारण जाँच में प्रगति हुई और गवाहों के बयान जाँच अधिकारी द्वारा दर्ज किए गए। इस तरह, धारा 161, सी.आर.पी.सी. के तहत गवाहों की जाँच में हुई देरी के लिए यह व्याख्या दी जाने के बाद, हम अपीलकर्ताओं की पक्ष से यह कहने के लिए रुचि नहीं रखते कि धारा 161, सी.आर.पी.सी. के तहत बयान दर्ज करने में हुई देरी के कारण अभियोजन साक्षियों की गवाहियों पर भरोसा नहीं किया जाना चाहिए।

20. हम श्री शरण की उस दलील को भी स्वीकार करने में असमर्थ हैं कि PW-3 और PW-4 की गवाही पर विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय ने भरोसा नहीं करना चाहिए जब यह सबूत दिखाने वाले थे कि PW-3 और PW-4 के बीच एक ओर और अपीलकर्ताओं के बीच दुश्मनी थी। जब गवाह और आरोपी के बीच पहले से ही दुश्मनी होती है, तो

न्यायालय को गवाह की गवाही को स्वीकार करने से पहले उसे ध्यानपूर्वक जाँचना होता है, लेकिन केवल ऐसी दुश्मनी के कारण न्यायालय गवाह की गवाही को पूरी तरह से खारिज नहीं कर सकती [देखें राज्य उत्तर प्रदेश बनाम किशनपाल और अन्य (2008) 16 एससीसी 73]। इसके अलावा, कुछ स्थितियों में एक अपराध के पीड़ित के संबंधियों के साथ संबंध न रखने वाले गवाह पाए जाना कठिन है। यह ऐसी स्थिति है जहां अपीलकर्ता ने PW-3 के घर पर परिवादी (PW-3) के घर पर सुबह 5.00 बजे 29.10.1991 को पहुंचकर उसके परिवार के सात सदस्यों को उठा लिया और इस घटना को 5.00 बजे देखने वाले व्यक्ति को पाना अक्टूबर के आखिरी हिस्से के दौरान मुश्किल है। इसके अलावा, एक अपीलकर्ता डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस था और इसलिए यहां तक कि अगर कोई ने भी घटना को देखा होता, तो वह जाँच अधिकारी या न्यायालय के सामने घटना का वर्णन करना पसंद नहीं करता। इस तरह की स्थिति में, न्यायालय को उन गवाहों के सबूतों को सावधानी से और सतर्कता से विचार करना होता है जिन्होंने आरोपियों के साथ दुश्मनी हो सकती है। इस सावधानीपूर्ण और सतर्क विचारण के बाद, यह कहना कठिन है कि PW-3 के सबूतों को खारिज कर दिया जाए कि अपीलकर्ता ने 29.10.1991 को सुबह 5.00 बजे उसके परिवार के सात सदस्यों को उसके घर से उठा लिया था, विशेषकर जब इसे PW-4 के सबूतों के साथ-साथ 19.01.1992 की शिकायत (Ext. PB) के साथ पुष्टि की जाती है, जो PW-3 के बयान के

रूप में पंजीकृत थी। हमारी विचारणीय राय में, इसलिए, विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय ने PW-3 और PW-4 के सबूतों को PW-3 और PW-4 के बीच एक ओर और अपीलकर्ताओं के बीच दुश्मनी के आधार पर खारिज करने का कोई कारण नहीं दिया था।

21. हम अब श्री शरण के उस सुझाव पर विचार कर सकते हैं कि PW-3 के बयान में जांच के दौरान धारा 161 सी.आर.पी.सी. के तहत दर्ज किए गए बयानों के दौरान सुधार हुए थे। धारा 162, सी.आर.पी.सी. के तहत व्याख्या यह प्रदान करती है कि धारा 161, सी.आर.पी.सी. के तहत पुलिस अधिकारी द्वारा दर्ज किए गए बयान में किसी तथ्य या परिस्थिति को व्यक्त करने में चूक हो सकती है यदि वही महत्वपूर्ण प्रतीत होता है और अन्यथा विशिष्ट परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए प्रासंगिक होता है, जिसमें ऐसी चूक होती है और यह कि कोई चूक विशेष परिप्रेक्ष्य में विरोधाभास है या नहीं, यह एक तथ्य का प्रश्न होगा। इस प्रकार, जब तक किसी गवाह के धारा 161, सी.आर.पी.सी. के तहत दर्ज किए गए बयान में चूक महत्वपूर्ण और प्रासंगिक नहीं होती है, जिस परिप्रेक्ष्य में चूक होती है, तो यह न्यायालय में दर्ज गवाह के सबूतों के साथ विरोधाभास नहीं होगा। PW-3 का सबूत है कि 29.10.1991 को अपीलकर्ता बलदेव सिंह ने अपीलकर्ता बलविंदर सिंह के साथ बीस से पच्चीस व्यक्तियों के साथ उसके घर पर तीन से चार वाहनों में आकर सधु सिंह (उसके पिता), हरदेव सिंह (उसके बेटे), गुरदीप सिंह (उसके भाई), अमनजीत सिंह (उसके बेटे),

शरणजीत सिंह (उसके भाई, सज्जन सिंह के बेटे), दविंदर सिंह और सुखदेव सिंह (उसके भाई खजान सिंह के बेटे) कुल सात व्यक्तियों को जिप्सी में बैठाया और अपीलकर्ता ने इन सात व्यक्तियों को अपने साथ ले लिया। 29.10.1991 को उसके घर से उसके परिवार के सात सदस्यों को उठाने और उसके परिवार के इन सात सदस्यों के नामों के बारे में PW-3 के बयान में धारा 161 Cr.P.C. के तहत दर्ज की गई जानकारी में कोई चूक नहीं है। PW-3 के धारा 161 Cr.P.C. के तहत दर्ज किए गए बयान में चूक वाहनों की प्रकृति, संख्या और रंग और आए हुए पुरुषों की संख्या के संबंध में है, साथ ही 29.10.1991 की उपरोक्त घटना के बाद क्या हुआ इसके बारे में भी है। हमारे विचार में, विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय ने इन चूकों पर सही ढंग से विचार किया है और इन्हें धारा 162, सी.आर.पी.सी. के तहत व्याख्या के तहत विरोधाभासों को दर्शाने वाली महत्वपूर्ण चूक नहीं मानी हैं। हमारे विचार में, इसलिए, उच्च न्यायालय ने सही विवेचना के आधार पर अपीलकर्ताओं की धारा 364 और 452 आईपीसी के तहत सजा को बरकरार रखा है।

22. हम अब श्री शरण के उस तर्क पर आ सकते हैं कि पत्रावली पर कोई भी सबूत नहीं है जो यह दिखाता है कि अपीलकर्ता द्वारा अपहरण किए गए सात व्यक्तियों की अपीलकर्ता द्वारा हत्या की गयी है।

23. हम पाते हैं कि पीडब्ल्यू-3 ने अपने साक्ष्य में कहा है: "हमारे सभी व्यक्ति जिन्हें अगवा किया गया था, उन्हें पीएस फतेहगढ़ चुरियां में उपस्थित पाया गया और उन्हें वहां 10 दिनों तक रखा गया। हम इस अवधि के दौरान उनसे मिलते रहे। उनकी हालत बहुत खराब थी। हम उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उन्हें भोजन और वस्त्र आदि पहुंचाने के लिए जाते थे। फिर इन व्यक्तियों को फतेहगढ़ चुरियां से कलानौर भेज दिया गया। मैं और मेरे रिश्तेदार जरनैल सिंह, कुलदीप सिंह, सज्जन सिंह भी उस पुलिस स्टेशन में जाकर हमारे व्यक्तियों से मिलते थे। हमने पाया कि इन सभी व्यक्तियों को कठोर पिटाई की गई थी और उनमें से गुरदीप सिंह, मेरा भाई और अमनजीत सिंह, उसका बेटा, दूसरों की तुलना में अधिक गंभीर चोटें प्राप्त हुई थीं।"इन व्यक्तियों की हालत बहुत खराब थी। पीएस कलानौर में हमारे व्यक्तियों को दस दिन रखने के बाद, उन्हें पीएस फतेहगढ़ चुरियां में रखा गया। इसके बाद, 3 व्यक्तियों को पीएस डेरा बाबा नानक ले जाया गया और 4 को पीएस कहनुवाल ले जाया गया। साधु सिंह, गुरदीप सिंह और अमनजीत सिंह को पीएस डेरा बाबा नानक में रखा गया, जबकि अन्य 4 को पीएस कहनुवाल में रखा गया। हम इन पुलिस स्टेशनों में भी उनसे समय-समय पर मिलते रहे। 08.12.1991 को 4 व्यक्तियों, अर्थात्, हरदेव सिंह, दविंदर सिंह, सुखदेव सिंह और शरणजीत सिंह को कहनुवाल पुलिस स्टेशन से पीएस सादिक फरीदकोट में स्थानांतरित किया गया। "मैंने उल्लेख किया कि हम उनसे

मिलते रहे जब वे पुलिस स्टेशन फतेहगढ़ चुरियां में 10 दिनों के लिए हिरासत में थे और उनकी हालत बहुत खराब थी और हम वहां जाकर उनकी जरूरतों के लिए भोजन और वस्त्र आदि पहुंचाने का काम करते थे।" "मेरे न्यायालय में दिए गए बयान में मैंने उल्लेख किया था कि हम कलानौर, फतेहगढ़ चुरियां आदि में विभिन्न पुलिस स्टेशनों पर अपने पुरुषों से मिलते रहे थे और हम उन्हें भोजन आदि भी उपलब्ध करा रहे थे।" इस प्रकार, पीडब्ल्यू-3 के साक्ष्य के अनुसार, जब उनके परिवार के सात सदस्यों का अपहरण किया गया, तो उन्होंने उनसे विभिन्न पुलिस स्टेशनों पर मुलाकात की और उन्हें उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए भोजन और वस्त्र आदि प्रदान किए।

24. हम पाते हैं कि पीडब्ल्यू-4 ने अपने बयान में कहा है: "हमने फिर से आरोपी बलदेव सिंह से संपर्क किया और उसने हमसे कहा कि हमारे व्यक्तियों को वापस भेज दिया जाएगा जब उसका भाई मिल जाएगा। इसके बाद, हम बटाला के एसएसपी से संपर्क करते रहे ताकि हमारे पुरुषों को रिहा कराया जा सके क्योंकि आरोपी बलदेव सिंह उसके नियंत्रण में डीएसपी के रूप में काम कर रहा था। हालाँकि, एसएसपी सीता राम इस मामले को टालते रहे और वादा करते रहे कि वह हमारे पुरुषों को रिहा कर देंगे। हमारे पुरुषों को समय-समय पर पुलिस स्टेशन फतेहगढ़ चुरियां, कलानौर, फिर फतेहगढ़ चुरियां और फिर कहनुवाल और डेरा बाबा नानक में रखा गया। हम इन पुलिस स्टेशनों में अपने परिवारजन से समय-समय

पर मिलते रहे और हम अपने परिवारजनों को भोजन, कपड़े और अन्य खाद्य पदार्थ प्रदान करते रहे। इसके बाद 4 व्यक्तियों को पीएस सादिक भेज दिया गया।" "हमारे परिवारजन पुलिस स्टेशन के पास स्थित आवासीय छात्रावासों में रखे जाते थे और हम वहाँ उनसे मिलते थे। इन अवसरों पर जनता के अन्य लोग वहाँ मौजूद नहीं होते थे। मैंने अपने पुलिस बयान में उल्लेख किया था कि हमारे व्यक्तियों को पुलिस स्टेशन फतेहगढ़ चुरियां ले जाया गया क्योंकि हमारे परिवारजनों को हमने बाद में देखा था।"इसलिए, पीडब्ल्यू-4 का साक्ष्य भी यह है कि अपीलकर्ताओं द्वारा उठाए गए सात व्यक्तियों को विभिन्न स्थानों पर रखा गया था, जिसमें पुलिस स्टेशनों और पुलिस स्टेशन के पास स्थित आवासीय छात्रावास शामिल थे, और उनके परिवार के सदस्य उन्हें भोजन, कपड़े और अन्य वस्त्र प्रदान करते थे और उनसे मिलते थे।

25.हम आगे पाते हैं कि पीडब्ल्यू-5 ने अपने साक्ष्य में कहा है: "मैं फिर गुरदासपुर गया। फिर मैंने सुना कि हमारे परिवारजन पुलिस स्टेशन कहनुवाल में रखे गए थे। मैं वहां गया और मैं केवल 4 व्यक्तियों को वहां पा सका। अन्य 3 व्यक्ति अर्थात् साधु सिंह, उसके बेटे गुरदीप सिंह और गुरदीप के बेटे वहां नहीं थे।" "मैंने यह भी बताया था कि मैं, इंदर सिंह, सज्जन सिंह और उनकी पत्नी, सज्जन सिंह के भाई ने पीएस कलानौर जाकर 7 व्यक्तियों से मुलाकात की थी।" "मैंने अपने बयान में पुलिस के सामने बताया था कि हम पीएस कहनुवाल गए थे और वहां 4 व्यक्तियों से

मिले थे।" "मैंने पीएस कलानौर के एसएचओ से मुलाकात नहीं की क्योंकि एसएचओ कभी भी हमें हमारे परिवारजनों से मिलने की अनुमति नहीं देता था। मैंने स्वेच्छा से स्पष्ट किया कि मैंने उनसे चुपके से मुलाकात की, जब एक हेड कांस्टेबल जो पहले क़ुआदियाँ में पोस्टेड रह चुका था, ने हमें उनसे मिलने में मदद की। मैं उसका नाम नहीं बता सकता। हेड कांस्टेबल ने हमारे 7 सदस्यों को उस विशेष कमरे से बाहर निकाला, ताकि हम उनसे मिल सकें। हालांकि, यह सब पुलिस स्टेशन के परिसर में हुआ था। हम वहां दिन के समय गए थे। वहां अन्य पुलिस अधिकारी और प्रहरी भी थे। यह गलत है कि मैंने झूठे साक्ष्य दिए हैं।" "हम पीएस कहनुवाल गए थे। वहां मेन हेड कांस्टेबल था। मैंने उसे बताया कि मैं अपने परिवारजनों से मिलना चाहता हूँ जो पुलिस स्टेशन के संगठित क्षेत्र में बंद थे, और कही गई वह MHC ने मुझे बताया कि मैं उनसे जल्दी मिलूं क्यूंकि परिसर क्षेत्र में बहुत सख्ती है, इसलिए मैं जल्दी मिलकर वहां से चला जा सकता हूँ।" इस प्रकार, पीडब्ल्यू-5 के साक्ष्य का भी यह है कि उन्होंने अपीलकर्ताओं द्वारा अपहृत होने के बाद अलग-अलग पुलिस स्टेशनों में सात व्यक्तियों से मिले, जहां अन्य पुलिस अधिकारी और प्रहरी भी थे।

26. हम यह भी पाते हैं कि पीडब्ल्यू-6, जो पीडब्ल्यू-3 का बेटा था और अमृतसर में पुलिस कांस्टेबल के रूप में काम कर रहा था, ने अपने साक्ष्य में कहा है: "08.01.1992 को मैं बस स्टैंड के पास की दुकानों के पास मौजूद था। मैंने सड़क पर जा रही एक पुलिस जिप्सी देखी। मैंने देखा

कि उस वाहन के शरीर में मेरा भाई हरदेव सिंह बैठा हुआ था। उसने मुझे अपने हाथ से एक संकेत भी दिया। उस वाहन में अन्य व्यक्ति भी थे, लेकिन मैं केवल अपने भाई को देख सका। मैंने उस वाहन का पीछा करने की कोशिश की लेकिन भीड़ के कारण मैं वाहन तक नहीं पहुंच सका, और वह निकल गई। उसी दिन मैंने अपने पिता को एक संदेश भेजा कि मैंने अपने भाई को एक वाहन में ले जाते हुए देखा है। पुलिस ने मेरा बयान भी जांच के दौरान दर्ज किया।"इस प्रकार, पीडब्ल्यू-6 ने भी अमृतसर में एक पुलिस जिप्सी में अपने भाई को बैठा हुआ देखा था।

27. इस प्रकार, हम पाते हैं कि पीडब्ल्यू-3, पीडब्ल्यू-4, पीडब्ल्यू-5 और पीडब्ल्यू-6 द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य यह है कि अपीलकर्ताओं द्वारा अपहृत सात व्यक्तियों को विभिन्न पुलिस स्टेशनों और पुलिस स्टेशन के पास स्थित आवासीय छात्रावासों में पाया गया था। इस साक्ष्य पर, न्यायालय यह नहीं कह सकता है कि दो अपीलकर्ताओं ने सात अपहृत व्यक्तियों की हत्या की है, केवल इसलिए कि सात व्यक्तियों का पता नहीं चला है या वे लापता हैं। राज्य के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि अपीलकर्ता बलदेव सिंह अपने क्षेत्र में सभी पुलिस स्टेशनों पर नियंत्रण रखता था, लेकिन न्यायालय के सामने कोई सामग्री प्रस्तुत नहीं की गई है जिससे पता चल सके कि कौन-कौन से पुलिस स्टेशन अपीलकर्ता बलदेव सिंह के नियंत्रण में थे। न्यायालय के सामने कोई सामग्री प्रस्तुत नहीं की गई है जिससे स्थापित हो सके कि आखिरी पुलिस स्टेशन, जिसमें सात व्यक्तियों में से

कोई भी या सातों व्यक्ति रखे गए थे, अपीलकर्ता बलदेव सिंह और अन्य अपीलकर्ता बलविंदर सिंह के नियंत्रण में थे। पीडब्ल्यू-3 के साक्ष्य से हम पाते हैं कि अपहरण के समय पंजाब राज्य में आतंकवाद फैल रहा था और पुलिस आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही थी। जब अपीलकर्ताओं द्वारा अपहृत सात व्यक्तियों अपने अपहरण के तुरंत बाद लापता नहीं हुए और उन्हें पंजाब राज्य के विभिन्न पुलिस स्टेशनों में देखा गया और उनमें से एक को अमृतसर में एक जिप्सी में जाते हुए भी देखा गया, तो न्यायालय यह नहीं कह सकता कि सात अपहृत व्यक्ति अंतिम बार अपीलकर्ताओं की हिरासत में थे और इसलिए उन्हें साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के तहत भार मुक्त होना चाहिए और यह स्पष्ट करना चाहिए कि उन्होंने सात अपहृत व्यक्तियों के साथ क्या किया। अभियोजन पक्ष को अपीलकर्ताओं की हिरासत में सात अपहृत व्यक्तियों को आखिरी बार देखे जाने को प्रमाणित करने के लिए पुलिस कर्मियों या पुलिस स्टेशन के बीच से गवाहों की परीक्षा करनी चाहिए थी। ऐसे साक्ष्य के पेश न होने से, हमारे विचार में, अपीलकर्ताओं के खिलाफ विचारण न्यायालयऔर उच्च न्यायालय द्वारा धारा 302 IPC के तहत पुष्ट की गई दोष सिद्धि का निष्कर्ष विधि एवं तथ्यों पर सही नहीं है।

28. इसलिए, हम दो अपीलकर्ताओं की धारा 302 सपठित 120-B, भा.प.सं. के तहत दोष सिद्धि को अपास्त करते हैं, लेकिन धारा 364 और 452, भा.प.सं. के तहत अपीलकर्ताओं की दोष सिद्धि को पुष्ट करते हैं।

विचारण न्यायालय ने धारा 452, भा.प.सं. के तहत अपराध के लिए तीन वर्षों की कठोर कारावास और 3000/- रुपये का जुर्माना और धारा 364, भा.प.सं. के तहत अपराध के लिए पांच वर्षों की कठोर कारावास और 4000/- रुपये का जुर्माना लगाया है, और उच्च न्यायालय ने उपरोक्त दोनों अपराधों के लिए दी गई सजाएं यथावत रखी हैं। हम धारा 452, भा.प.सं. के तहत सजा और जुर्माने को यथावत रखते हैं। लेकिन धारा 364, भा.प.सं. के तहत सजा और जुर्माने के बारे में, हम पाते हैं कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 220 के उदाहरण (h) में यह बताया गया है कि जहाँ एक आरोपी तीन व्यक्तियों के खिलाफ एक ही अपराध करता है, तो उसे तीन अपराधों के लिए आरोपित किया जा सकता है। चूंकि सात व्यक्तियों को अपीलकर्ताओं द्वारा अपहृत किया गया था, इसलिए अपीलकर्ता धारा 364, भा.प.सं. के तहत सात अपराधों के लिए दोषी थे, और उन्हें धारा 364, भा.प.सं. के तहत इन प्रत्येक अपराधों के लिए सजा दी जानी चाहिए थी। इसलिए, हम आदेश देते हैं कि विचारण न्यायालयद्वारा लगाया गया जुर्माना राशि प्रत्येक अपहरण के सात अपराधों के लिए 4000/- रुपये होगी और कठोर कारावास की अवधि प्रत्येक अपहरण के सात अपराधों के लिए पांच वर्ष होगी और ये पांच वर्ष की कठोर कारावास की अवधि प्रत्येक अपहरण के सात अपराधों के लिए साथ-साथ नहीं चलेगी, बल्कि क्रमिक रूप से चलेगी। यदि 4000/- रुपये की जुर्माना राशि नहीं चुकाई जाती है, तो

अपीलकर्ताओं को एक और वर्ष की कठोर कारावास की सजा भुगतनी होगी। अपीलें उक्तानुसार आंशिक रूप से स्वीकार की जाती हैं ।

RP अपीलों को आंशिक रूप से स्वीकार किया गया ।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी श्री मोहित शर्मा (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।

Translated By

MOHIT SHARMA, RJS (RJ00641)

ADJ No.1, Aburoad, Sirohi (Rajasthan)

04.11..2023

CERTIFICATE

NAME OF THE HIGH COURT: RAJASTHAN HIGH COURT

Sl. No.	Name of the Judicial	Bank details of	Citation of the original English	Cause Title	Case No.	Date of Judgm	Total Number of pages	Total amount

	Officer/ Lawyer/ Translator	the Judicial Officer/ Lawyer/ Translator (including A/c No., Name of the Bank, IFSC) and PAN No.	e-SCR Judgment translated			en t	of e-SCR Judgments translated / validated / corrected by the Translator Judicial Officer	payable (@Rs. 100 per page)
1	Mohit Sharma	Bank	(2013) 9	Baldev	Criminal	20.09.	26	

	RJS RJ 00641 ADJ No 1 Aburoad Sirohi Rajasthan	A/C: 61022584145 IFS Code : SBIN0010637 Branch: SBI, Tilak Nagar Jaipur. PAN: CQJPS4511F	S.C.R. page 547 PDF file Name 2013_9_547_572.pdf	Singh v. State of Punjab	Appeal No. 1303 of 2005 etc.	2013		